विचार बिन्दु

मन की प्रसन्नता से समस्त मानसिक और शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। –रामदास

पुस्तकालय कहाँ जा रहे हैं?

पिछले दिनों भारत के समाचार पत्रों में छपी एक खबर ने पुस्तक-प्रेमियों को चिंतित कर दिया। खबर का निहितार्थ यह था कि राजधानी दिल्ली के शास्त्री भवन में अवस्थित केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की लगभग साढ़े आठ लाख किताबें खतरे में हैं। असल में शास्त्री भवन को खाली किया जा रहा है और उसके नए ठिकाने में कदाचित इतनी सारी पुस्तकों के लिए पर्याप्त जगह न हो। इस पुस्तकालय की स्थापना कोलकाता में सन 1891 में इम्पीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में हुई थी और सन 1969 से यह शास्त्री भवन में अवस्थित है। पुस्तकालय की वेबसाइट के अनुसार इसमें लगभग साढ़े आठ लाख मुद्रित और मुद्रणेतर ग्रंथ हैं। कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय है। लेकिन इस पुस्तकालय में केवल सामान्य पुस्तकें नहीं हैं। इसमें दुर्लभ पुस्तकें, सरकारी दस्तावेज, जनगणना रिपोर्ट्स, बजट अभिलेख, संसदीय बहसें, भारत का राजपत्र और अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन हैं। यहाँ कुछ दुर्लभ सामग्री तो 1702 तक की है। कहा जा सकता है कि यह केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं, हमारी जीवित स्मृति का एक कोश है।

इस कोश के भविष्य को लेकर प्रबुद्ध जन का आशंकित होना स्वाभाविक ही था। उनकी आशंकाओं को खाद-पानी इस बात से भी मिला कि इसी केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का एक खंड-प्रादेशिक भाषाओं का खंड, जिसे तुलसी सदन पुस्तकालय कहा जाता था-सन 2011 में मंडी हाउस मेट्रो निर्माण के कारण बंद कर दिया गया था और उसकी दो लाख से अधिक किताबें लंबे समय तक डिब्बों में बंद पड़ी रहीं। यह संतोष की बात है कि इस पुस्तकालय के असमिया और कन्नड़ खंड के कुछ हिस्से तथा हिंदी खंड को भी आंशिक रूप से खोला गया है।

ये पंक्तियाँ लिखते-लिखते आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का एक बयान भी सामने आया है, जिसके अनुसार सेंट्रल विस्टा योजना में पुस्तकालय के लिए प्रावधान रखा गया है। कामना करें कि केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के इस विशाल एवं मूल्यवान संग्रह को लेकर हमारी आशंकाएँ निर्मूल साबित हों।

लेकिन इस पूरे प्रसंग में असली सवाल शायद यह नहीं है कि साढ़े आठ लाख किताबें कहाँ जाएँगी। असली सवाल यह है कि हमारे समाज में पुस्तकालय कहाँ जा रहे हैं।

कुछ लोग तो सीधे यह मानते हैं कि अब लोगों की पढ़ने की आदत लगभग खत्म हो गई है, इसलिए पुस्तकालयों की कोई जरूरत ही नहीं है। यह बहुत एकांगी और भ्रामक दृष्टिकोण है। बेशक आज पुस्तकों के बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं और तकनीक ने हमें पहले की तुलना में कहीं अधिक सूचना-संपन्न बना दिया है। इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धि ने सूचना तक हमारी पहुँच को असाधारण रूप से आसान भी कर दिया है। फिर भी यह मान लेना कि अब पुस्तकालय अप्रासंगिक हो गए हैं, ठीक नहीं होगा। आखिर एक किताब हमें केवल सूचना नहीं देती। वह हमें एक अनुभव से गुजारती है। वह हमें किसी विचार, किसी समय, किसी व्यक्ति और किसी समाज के साथ कुछ देर रहने का अवसर देती है। पढ़ना केवल जान लेना नहीं है; पढ़ना अपने भीतर किसी चीज को जगह देना भी है। तकनीक सूचना तक पहुँच आसान कर सकती है, लेकिन पुस्तक और पुस्तकालय का अनुभव अभी भी उससे अलग और महत्त्वपूर्ण है।

सूचना की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञान की जरूरत कम हो गई है। शायद उलटे, सूचना की इस बाढ़ में ज्ञान को पहचानने की जरूरत और बढ़ गई है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में 46,746 सार्वजनिक पुस्तकालय हैं। हमारे यहाँ पुस्तकालय चूँकि राज्य सरकारों का विषय हैं, इसलिए उनका रख-रखाव और संचालन राज्य सरकारें करती हैं। स्वाभाविक ही है कि अलग-अलग राज्यों में पुस्तकालयों की स्थिति भी अलग होगी। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मिशन ऑनलाइब्रेरीज संचालित हो रहा है। मार्च 2026 तक इसके अंतर्गत 28 राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों और 41 जिला पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 2465 पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

जहाँ तक हमारे अपने प्रांत राजस्थान की बात है, जयपुर स्थित डॉ। राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय को नेशनल मिशन ऑनलाइब्रेरीज के अंतर्गत 183.51 लाख रुपये और कोटा के राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को 63.46 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की जा चुकी है। सन 2025-26 में नेशनल मिशन ऑनलाइब्रेरीज का संशोधित बजट3,507 लाख रुपये था और इसमें से 3,309 लाख रुपये जारी किए गए, जबकि वास्तविक व्यय 3,244.08 लाख रुपये बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारें पुस्तकालयों पर ध्यान तो दे रही हैं।

> **यह देखना दुखद है कि अनेक सरकारी प्रयासों और भारी पूंजी निवेश के बावजूद देश के अधिकांश पुस्तकालय बदहाली के शिकार हैं। उनके अपर्याप्त, अप्रशिक्षित और उदासीन स्टाफ की वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, उनसे दूर भागते हैं। पुस्तकालयों को केवल भवन, अलमारियों और पुस्तकों के भण्डार के रूप में नहीं, एक जीवंत संस्था के रूप में देखने की जरूरत है।**

लेकिन यहीं एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। क्या पुस्तकालय को केवल पुस्तकों का भंडार मान लेना पर्याप्त होगा? सरकार बजट दे और किसी भवन में किताबें भर दी जाएँ-क्या यह पर्याप्त है? यह भी देखने की बात है कि क्या हम अपने पुस्तकालयों के प्रति आम जन में रुचि पैदा करने के लिए कुछ करते हैं? क्या पुस्तकालयों का विकास सामुदायिक केंद्रों के रूप में नहीं हो सकता? वहाँ तरह-तरह के आयोजन हों, आम जन आएँ और पुस्तकों को देखकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित हों। पुस्तकों और विचारों को केंद्र में रखकर गोष्ठियाँ हों। लोग पुस्तकों के बीच बैठकर चर्चाएँ करें और तब शायद किताबें भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करें। पुस्तकालय केवल किताबें रखने की जगह न होकर विचारों के मिलने-जुलने की जगह क्यों नहीं बन सकते? बहुत बड़ा सवाल यही कि जिस जगह किताबें हों, वहाँ केवल अलमारियाँ क्यों हों, वहाँ बातचीत क्यों न हो?

इधर हमारी सरकारें पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण पर खूब जोर दे रही हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पुस्तकों को कागज से हटाकर स्क्रीन तक ले जाकर ही हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जानी चाहिए। हमें हर संभव प्रयत्न इस बात का करना होगा कि लोग यह समझें कि इंटरनेट या एआई पुस्तकों और पुस्तकालयों का बेहतर विकल्प नहीं हैं। इनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सूचना और ज्ञान में जो अंतर है, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। और यह बात केवल भाषणों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभवों के द्वारा लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए।

एक बहुत रोचक बात यह है कि इन दिनों देश भर में जगह-जगह ऐसे साइन बोर्ड लगे नजर आते हैं जिन पर 'पुस्तकालय' या 'लाइब्रेरी' अंकित होता है। असल में यह इस शब्द का कुछ हद तक भ्रामक इस्तेमाल है। ये ठिकाने वास्तव में किराये पर दिए जाने वाले ऐसे स्थान होते हैं जहाँ विद्यार्थी बैठकर (अपनी) किताब पढ़ सकता है। वहाँ किताबों का कोई संग्रह नहीं होता। बेशक ये ठिकाने उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं जिनके घर में इतना एकांत नहीं है कि वे एकाग्र होकर पढ़ सकें। लेकिन यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतियोगी परीक्षा या रोजगार को ध्यान में रखकर की जाने वाली पढ़ाई की प्रकृति उस पढ़ाई से भिन्न होती है जिसकी हम व्यापक अर्थ में कामना करते हैं। एक में लक्ष्य परीक्षा पास करना हो सकता है, दूसरी में स्वयं को थोड़ा अधिक जानना, दुनिया को समझना और अपने भीतर प्रश्न पैदा करना होता है।

एक जगह ऐसी हो जहाँ किताबें केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, जीवन को थोड़ा बेहतर समझने के लिए भी पढ़ी जाएँ-शायद सार्वजनिक पुस्तकालय की सबसे बड़ी जरूरत यही है।

यह देखना दुखद है कि अनेक सरकारी प्रयासों और भारी पूंजी निवेश के बावजूद देश के अधिकांश पुस्तकालय बदहाली के शिकार हैं। उनके अपर्याप्त, अप्रशिक्षित और उदासीन स्टाफ की वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, उनसे दूर भागते हैं। पुस्तकालयों को केवल भवन, अलमारियों और पुस्तकों के भण्डार के रूप में नहीं, एक जीवंत संस्था के रूप में देखने की जरूरत है। उनका संचालन ऐसे समर्पित लोगों से करवाया जाना चाहिए जो स्वयं पुस्तकों से प्रेम करते हों और दूसरों को भी उनसे जोड़ने में रुचि रखते हों।

लेकिन इस काम को पूरी तरह सरकार पर छोड़ देना भी उचित नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह हो कि हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर गाँव में, हर शहर में पुस्तकालय हों, उनका एक जाल-सा बिछा हो और तकनीक के इस समय में वे सारे पुस्तकालय एक-दूसरे से जुड़े हों। अगर किसी पाठक को किसी दूसरे शहर के पुस्तकालय में अपनी रुचि की कोई पुस्तक दिखाई दे तो उसे वह पुस्तक सुलभ कराई जा सके। यह कोई बहुत बड़ा या अव्यावहारिक सपना नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं आम हैं।

मुझे इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यह लगती है कि पुस्तकों और पुस्तकालयों को तो बचाया ही जाए, पाठकों को भी बचाया जाए और, उससे भी आगे, पाठकों की वंश-वृद्धि के प्रयास किए जाएँ। आखिर पुस्तकालय किसके लिए हैं?किताबें अलमारियों में सुरक्षित रखी जा सकती हैं। उन्हें डिजिटल भी किया जा सकता है। दुर्लभ पुस्तकों को स्कैन करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जा सकता है। लेकिन अगर उन्हें पढ़ने वाले लोग ही नहीं बचे, तो पुस्तकालयों का अर्थ क्या रह जाएगा? पाठक बचे रहेंगे तो पुस्तकालय अपने आप पनपेंगे। यह कुछ-कुछ मांग और पूर्ति वाली बात है। इसलिए आज शायद सबसे बड़ी जरूरत नई पुस्तकें खरीदने से भी पहलेनए पाठक पैदा करने की है।

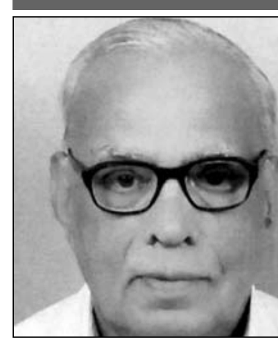
जिस समाज में हर घर में पुस्तकालय नहीं हो सकता, वहाँ हर बच्चे के लिए एक अच्छा सार्वजनिक पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए।

और शायद इसी कसौटी पर हमें अपने पुस्तकालयों को देखना चाहिए-हमारे पास कितनी किताबें हैं, यह महत्वपूर्ण है; लेकिन उन किताबों तक पहुँचने वाले कितने पाठक हैं, यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों में पेंशन का संकट और अकाल

लगभग 8,000 पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रश्न



डॉ. आर. एम. शर्मा

भारत में पेंशन केवल सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक धनराशि नहीं है। यह कर्मचारी के जीवनभर की सेवा के बदले मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा है। नौकरी के दौरान वर्षों तक सेवा देने के बाद वृद्धावस्था में नियमित आय का साधन समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में पेंशन व्यक्ति तथा उसके परिवार को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सम्मान और न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए पेंशन का समय पर भुगतान केवल वित्तीय विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा से जुड़ा प्रश्न है।

राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े लगभग 8,000 पेंशनरों की स्थिति इसी दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान में विलंब और वित्तीय संकट की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं। मूल प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालयों की वित्तीय कठिनाइयों का भार उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर क्यों पड़े, जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को समर्पित किया है?

पेंशन व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास -भारत में पेंशन व्यवस्था का विकास क्रमिक रूप से हुआ। औपनिवेशिक काल में पेंशन मुख्यत: सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के रूप में विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद इसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा से जोड़ा गया। संगठित क्षेत्र के विस्तार के साथ भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुईं। mployees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, Employees' Pension Scheme, 1995 Payment of Gratuity Act, 1972 इसी व्यापक कर्मचारी-सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों की पेंशन व्यवस्था भी इसी ऐतिहासिक विकास का हिस्सा है। विश्वविद्यालयों में पेंशन योजना का विकास लगभग 1990 के आसपास हुआ और राज्य सरकार के निर्णयों, निर्देशों तथा संबंधित पेंशन विनियमों के माध्यम से इसे संस्थागत रूप मिला। इसलिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में स्थापित पेंशन व्यवस्था की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता केवल सेवानिवृत्त कर्मचारी की निजी समस्या नहीं, बल्कि संस्था और सार्वजनिक नीति का प्रश्न है।

राज्य के बजट में पेंशन का स्थान -भारत सरकार और राज्य सरकारें पेंशन को नियमित बजटीय दायित्व के रूप में स्वीकार करती हैं। भारत सरकार के 2024-25 के वास्तविक व्यय में पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर लगभग 3.46 लाख करोड़ खर्च हुए। राजस्थान में 2024-25 का पेंशन व्यय लगभग 29,318 करोड़ रहा, जबकि 2025-26 के बजट में लगभग 33,882 करोड़ का प्रावधान किया गया। ईरदे पूं 2071-"Pension and Other Retirement Benefits"—में सुपरएन्नुएशन पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ग्रेच्युटी, फैमिली पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार पेंशन को एक नियमित और आवश्यक वित्तीय दायित्व मानती है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि राज्य विश्वविद्यालयों के पेंशनरों के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था क्यों विकसित नहीं की गई?

स्वायत्तता बनाम पेंशन की जिम्मेदारी -राज्य विश्वविद्यालयों को अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति वित्तीय दायित्वों में पूरी तरह अकेले छोड़ दिए जाएं। पिछले दशकों में अनेक विश्वविद्यालयों की अपनी आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ी, जबकि पेंशनरों की संख्या, पेंशन संशोधन और जीवन-यापन की लागत बढ़ती गई। परिणामस्वरूप कई विश्वविद्यालयों के लिए पेंशन दायित्व उनकी आंतरिक आय की तुलना में अधिक हो गया। यहीं मूल नीति प्रश्न सामने आता है-क्या किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय कमजोरी के कारण उसके कर्मचारियों की अर्जित पेंशन बाधित होनी चाहिए?

जिम्मेदारी किसकी- विश्वविद्यालय या राज्य सरकार? -इस संकट की जिम्मेदारी केवल किसी एक अधिकारी या विभाग पर डालना उचित नहीं होगा। यह संस्थागत उत्तरदायित्व का प्रश्न है। विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व पेंशन की गणना, स्वीकृति, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग और पेंशन फंड का प्रभावी प्रबंधन है। लेकिन यदि संरचनात्मक वित्तीय कमी के कारण हजारों पेंशनरों की नियमित पेंशन प्रभावित होती है, तो उच्च शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के सामने भी दीर्घकालीन नीति बनाने की जिम्मेदारी आती है।

राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सभी विश्वविद्यालयों की कुल पेंशन देयता कितनी है, प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास पेंशन फंड कितना है, पिछले वर्षों में कितनी सरकारी सहायता दी गई है और भविष्य की आवश्यकता कितनी होगी। वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार-सभी की अपनी भूमिका और जवाबदेही है।

लगभग 550 करोड़ का वार्षिक पेंशन दायित्व -उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में राजस्थान के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के लगभग 8,000 पेंशनरों की वार्षिक पेंशन आवश्यकता करीब 550 करोड़ बताई गई है। यह आंकड़ा संबंधित विश्वविद्यालयों के समेकित ऑडिटेड खातों से सत्यापित किया जाना चाहिए, लेकिन नीति के स्तर पर इसका महत्व स्पष्ट है। राज्य का कुल वार्षिक पेंशन व्यय हजारों करोड़ रुपये में है, जबकि विश्वविद्यालय पेंशनरों की कथित वार्षिक आवश्यकता लगभग 550 करोड़ है। अत: समस्या केवल धनराशि की उपलब्धता की नहीं, बल्कि वित्तीय उत्तरदायित्व और स्थायी व्यवस्था की भी है।

सरकारी और विश्वविद्यालय पेंशन में अंतर क्यों? -यदि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन मिलती है, तो राज्य विश्वविद्यालयों के पेंशनरों के लिए अलग और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था क्यों हो-इसका स्पष्ट नीतिगत उत्तर आवश्यक है। यह प्रश्न किसी एक विश्वविद्यालय के विरुद्ध नहीं, बल्कि राजस्थान की समग्र उच्च शिक्षा वित्त नीति से जुड़ा है।

केंद्र की व्यवस्था से मिलने वाला नीति-संदेश -केंद्र सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों, IITs, NITs, IISERs तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के अनुदान देती है। Grants-in-Aid-Salaries और अन्य आवर्ती सहायता के माध्यम से स्वायत्त संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं में सरकारी भागीदारी होती है। यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों की पेंशन के लिए कानूनी मिसाल नहीं है, लेकिन यह अवश्य दिखाती है कि स्वायत्तता और पूर्ण वित्तीय आत्मनिर्भरता एक ही बात नहीं हैं।

राजस्थान के सामने चार संभावित समाधान -राजस्थान सरकार के सामने समाधान के कई विकल्प हैं। पहला, प्रत्येक विश्वविद्यालय के पेंशन दायित्व के लिएपेंशन ब्लॉक ग्रांटदिया जा सकता है। दूसरा, विश्वविद्यालय पेंशनरों को राज्य कोष से सीधे भुगतान करने काट्रेजरी मॉडल अपनाया जा सकता है। तीसरा, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार निर्धारित अनुपात में योगदान देकर साझा अंशदान मॉडल बना सकते हैं। चौथा, राज्य स्तर पर एक ळहग्नेग्रू झहेग्दह ण्देज्ले बनाया जा सकता है, जिसमें प्रारंभिक सरकारी सहायता के साथ विश्वविद्यालयों का निर्धारित योगदान हो। हालांकि किसी भी मॉडल को लागू करने से पहले प्रत्येक विश्वविद्यालय की वास्तविक पेंशन देयता, पेंशनरों की संख्या, उपलब्ध पेंशन फंड, आय, सरकारी सहायता तथा पिछले वर्षों के व्यय का स्वतंत्र वित्तीय परीक्षण आवश्यक है।

अन्य राज्यों से सीखने की जरूरत -राजस्थान को अन्य राज्यों में राज्य विश्वविद्यालयों के पेंशन दायित्व के वित्तपोषण का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। इसमें पेंशन का कानूनी आधार, पेंशन फंड, राज्य अनुदान, ट्रेजरी भुगतान, विश्वविद्यालय की आय, पेंशनरों की संख्या, वार्षिक व्यय और भुगतान में विलंब जैसे पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। इससे राजस्थान के लिए तथ्य-आधारित, पारदर्शी और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल तैयार किया जा सकता है।

तत्काल वित्तीय समीक्षा और स्थायी नीति जरूरी -तत्काल आवश्यकता यह है कि राज्य सरकार सभी राज्य विश्वविद्यालयों से एक समान प्रारूप में पेंशन की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करे। वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय प्रशासन और लेखा-परीक्षा संस्थाओं के सहयोग से ळहग्नेग्रू झहेग्दह इर्गहेंहर्मेर्ट ग्नै तैयार किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक विश्वविद्यालय की वर्तमान पेंशन देयता, उपलब्ध निधि, आय, सरकारी सहायता और भविष्य की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वविद्यालय की अस्थायी वित्तीय कठिनाई के कारण वर्तमान पेंशन भुगतान बाधित नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को विश्वविद्यालय पेंशन के लिए स्पष्ट और दीर्घकालीन वित्तीय नीति घोषित करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक वर्ष पेंशनरों को अनिश्चितता, प्रतीक्षा और प्रशासनिक पत्राचार का सामना न करना पड़े।

पेंशन संकट का समाधान अब नीति से होना चाहिए - राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों मेंपेंशन का संकट केवल लगभग 8,000 पेंशनरों की समस्या नहीं है। यह उच्च शिक्षा की वित्तीय संरचना, राज्य की सामाजिक-सुरक्षा नीति और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति सार्वजनिक दायित्व से जुड़ा व्यापक प्रश्न है। पेंशन किसी पर कृपा नहीं, बल्कि दीर्घकालीन सेवा से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा है।

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, उसकी वित्तीय क्षमता और राज्य सरकार की जिम्मेदारी-इन तीनों के बीच संतुलित और स्थायी व्यवस्था बनाना समय की आवश्यकता है। पेंशन ब्लॉक ग्रांट, ट्रेजरी भुगतान, साझा अंशदान अथवा स्थायी पेंशन कॉर्पस-राज्य के पास अनेक विकल्प हैं।

अब आवश्यकता केवल एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति-निर्णय की है, ताकि विश्वविद्यालय सुचारु रूप से कार्य कर सकें और उनके सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मान, निश्चितता और आर्थिक सुरक्षा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

-प्रो. डॉ. आर. एम. शर्मा,
पूर्व विभागाध्यक्ष,
जयनारायण व्यास विवि, जोधपुर

भाट की बही में दर्ज है शेढल माता की 770 वर्ष पुरानी आराधना का इतिहास



अचलदास डांगरा

संवत 1313 (ईस्वी सन् 1256) में श्री जयदेव डांगरा ने करवाई थी कुलदेवी की प्राण प्रतिष्ठा, डांगरा, पसारी एवं गोलकीया माहेश्वरी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र

जैसलमेर। स्वर्णनगरी जैसलमेर की पहचान केवल उसके स्वर्णिम दुर्ग, भव्य हवेलियों और ऐतिहासिक स्थापत्य से ही नहीं है, बल्कि यहां सदियों से चली आ रही धार्मिक एवं पारिवारिक परंपराएं भी इसकी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसी ही प्राचीन आस्था और परंपरा श्री शेढल माता की है, जिसका उल्लेख पारिवारिक विवरण तथा भाट की बही में सुरक्षित बताया जाता है।

उपलब्ध पारंपरिक विवरण के अनुसार संवत 1313, अर्थात ईस्वी सन् 1256 में श्री जयदेव डांगरा ने श्री शेढल माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। इस आधार पर वर्ष 2026 में इस परंपरा को लगभग 770 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। डांगरा, पसारी एवं गोलकीया माहेश्वरी समाज में श्री शेढल माता को आराध्य कुलदेवी के रूप में श्रद्धा के साथ पूजा जाता है।

भाट की बही में सुरक्षित है परंपरा का इतिहास -राजस्थान की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में भाटों की बहियों का विशेष महत्व रहा है। परिवारों की वंशावली, महत्वपूर्ण घटनाओं, सामाजिक संबंधों और धार्मिक परंपराओं का विवरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी इन बहियों में सुरक्षित रखा जाता रहा है।

डांगरा परिवार से संबंधित भाट की बही में उपलब्ध विवरण भी श्री शेढल माता की प्राचीन आराधना से जुड़ी परंपरा की स्मृति को संजोए हुए है। ऐसे पारंपरिक स्त्रोत आधुनिक इतिहास के औपचारिक अभिलेखों से अलग प्रकृति के होते हैं, लेकिन परिवार और समाज की स्मृति, वंश परंपरा तथा धार्मिक आस्था को समझने में इनका अपना महत्व है। इसलिए भाट की बही में दर्ज विवरण को सुरक्षित रखना केवल एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस सामाजिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है।

770 वर्षों से चली आ रही आस्था की परंपरा -यदि संवत 1313 को ईस्वी सन् 1256 माना जाए, तो वर्ष 2026 में श्री शेढल माता की इस परंपरा को लगभग 770 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे कालखंड में राजघराने बदले, शासन व्यवस्थाएं बदलीं, जैसलमेर ने अनेक ऐतिहासिक दौर देखे और सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन आया, लेकिन कुलदेवी के प्रति श्रद्धा की परंपरा पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ती रही। डांगरा परिवार में भी श्री शेढल माता के प्रति आस्था निरंतर बनी रही। स्वर्गीय जीतमल पुत्र जीवनलाल डांगरा कुलदेवी के नियमित श्रद्धालु रहे। वे नियमित रूप से मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए जाते थे और अन्य श्रद्धालुओं को भी कुलदेवी के दर्शन के लिए प्रेरित करते थे। उनके लिए मंदिर केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि पूर्वजों की आस्था, पारिवारिक संस्कार और समाज की धार्मिक परंपरा से जुड़ा केंद्र था।

आज भी नियमित होती है ज्योत और आरती -समय के परिवर्तन के बावजूद श्री शेढल माता की आराधना की परंपरा आज भी जारी है। मंदिर में नियमित रूप से पूजा-अर्चना, ज्योत एवं आरती होती है। वर्तमान पुजारी रमेश महाराज द्वारा नित्य ज्योत एवं आरती की जाती है।

तकनीक के इस दौर में धार्मिक परंपरा ने भी नया माध्यम अपना लिया है। 'शेढल माता' व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन ज्योत एवं आरती के दर्शन के दृश्य देश-विदेश में रहने वाले समाजबंधुओं और श्रद्धालुओं तक पहुंचते हैं। इससे जैसलमेर से दूर रहने वाले परिवार भी अपनी कुलदेवी की दैनिक आराधना से जुड़े रहते हैं।

आस्था से इतिहास और इतिहास से नई पीढ़ी का जुड़ाव -श्री शेढल माता की यह परंपरा केवल पूजा-अर्चना की कहानी नहीं है। यह परिवार, समाज और पूर्वजों से जुड़े

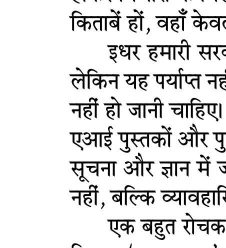


संस्कारों की ऐसी विरासत है, जो लगभग 770 वर्षों के लंबे सफर के बाद भी वर्तमान पीढ़ी तक पहुंची है।

संवत 1313 यानी ईस्वी सन् 1256 में श्री जयदेव डांगरा द्वारा करवाई गई प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा पारंपरिक विवरण, भाट की बही में सुरक्षित स्मृतियां, स्वर्गीय जीतमल डांगरा जैसे श्रद्धालुओं की नियमित दर्शन-सेवा और आज भी जारी ज्योत-आरती-ये सभी मिलकर श्री शेढल माता की आराधना की निरंतरता को सामने रखते हैं। आज आवश्यकता है कि ऐसी पारिवारिक एवं सामाजिक ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जाए। भाट की बहियों, पुराने हस्तलिखित दस्तावेजों और पारिवारिक अभिलेखों का संरक्षण किया जाए तथा उनकी प्रतिलिपियां और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएं। इससे आने वाली पीढ़ियां अपने कुल, कुलदेवी, पूर्वजों और धार्मिक-सामाजिक परंपराओं के इतिहास से परिचित हो सकेंगी। जैसलमेर की पहचान केवल पत्थरों में लिखे इतिहास से नहीं, बल्कि ऐसी जीवंत आस्थाओं से भी है, जिन्हें पीढ़ियां अपने संस्कारों में संजोकर आगे बढ़ाती रही हैं। श्री शेढल माता की लगभग 770 वर्ष पुरानी आराधना इसी जीवंत विरासत का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

–अचलदास डांगरा,
वरिष्ठ पत्रकार, जेठा पाड़ा,
जैसलमेर

राशिफल



पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 5 अक्टूबर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत-2083, पुष्य नक्षत्र रात्रि 11:09 तक, शिव योग प्रात: 9:51 तक, वणिज करण दिन 3:01 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

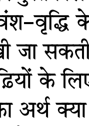
ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 10:09 तक है। ज्वालामुखी योग रात्रि 11:09 से रात्रि 2:08 तक है। भद्रा दिन 3:01 से रात्रि 2:08 तक रहेगी। आज दशमी का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– अमृत सूर्योदय से 7:52 तक, शुभ 9:20 से 10:48 तक, चर 1:43 से 3:11 तक, लाभ अमृत 3:11 से सूर्यास्त तक।

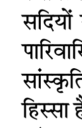
राहुकाल– 7:30 से 9:00 तक, सूर्योदय 6:24, सूर्यास्त 6:06

मेष



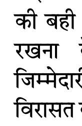
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

वृष



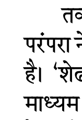
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आज अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन



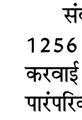
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कर्क



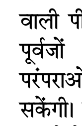
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह



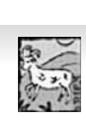
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

कन्या



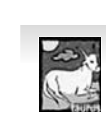
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

तुला



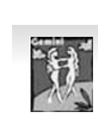
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों उचित सफलता मिलेगी।

वृश्चिक



परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु



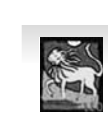
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मकर



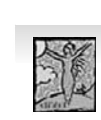
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कुंभ



विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि होगी।

मीन



ेव्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।